

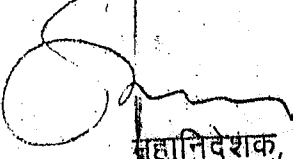
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: व।अ(ड) भ्र.नि.ब्यूरो/सामान्य/२००६/५१/५५५-६१८
∴ विज्ञप्ति ∴

दिनांक: 18-02-2006

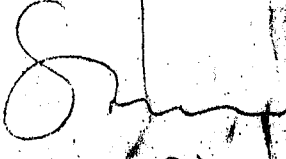
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-22) की धारा-4 की उप धारा (1) के अनुच्छेद (बी) के अन्तर्गत संलग्न विभागीय मैनुवल सर्व साधारण की जानकारी हेतु एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

विभागीय मैनुवल की प्रति ब्यूरो मुख्यालय एवं सभी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ओ.पी.) राजस्थान के अधिकारियों के कार्यालयों में सर्व साधारण के अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-


महानिदेशक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ :-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2 महानिदेशक, राजस्थान पुलिस, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
- 3 माननीय विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम
- 4 महानिरीक्षक पुलिस, (प्रथम / द्वितीय) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर / उदयपुर / जोधपुर।
- 5 उप महानिरीक्षक पुलिस, (प्रथम / द्वितीय) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
- 6 पुलिस अधीक्षक, (प्रथम / द्वितीय) भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर / कोटा / बीकानेर / भरतपुर एवं अजमेर।
- 7 समस्त अति० / उच्च अधीक्षक पुलिस, भ्र.नि.ब्यूरो
- 8 सहायक लेखाधिकारी, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर।
- 9 सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी
- 10 रक्षित पत्रावली
- 11 नोटिस बोर्ड भ्र.नि.ब्यूरो मुख्यालय जयपुर।


महानिदेशक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
राजस्थान, जयपुर।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) के अन्तर्गत विभागीय मैनुवेल

1 विभाग का संगठन, उद्देश्य एवं कार्य :

भ्रष्टाचार उन्मूलन की राज्य सरकार की घोषित नीति को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रसारित अधिनियम/आदेश/निर्देश यथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रदत्त अधिकारों व निर्धारित प्रक्रियानुसार भ्रष्ट राज्य सेवकों को दण्डित करवाने का महत्वपूर्ण कार्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा किया जा रहा है। ब्यूरो का प्रशासनिक विभाग, गृह विभाग है। ब्यूरो द्वारा मुख्यतः रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े गये लोक सेवकों/राज्य सरकार के फण्ड का दुरुपयोग कर पद का दुरुपयोग कर राज्य सरकार को हानि पहुंचाने एवं भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा आय से अधिक सम्पत्तियाँ अर्जित करने पर, ब्यूरो द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाती है। इसी प्रकार भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें मिलने पर शिकायतों की जांच पड़ताल के पश्चात प्राथमिकी दर्ज करने का भी प्रावधान है। प्राथमिकी जाँच से तथ्य सही पाये जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाकर विस्तृत अनुसंधान किया जाता है।

2. कार्य सम्पादन :

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान द्वारा निम्नांकित कार्य सम्पादित किये जाते हैं :-

- 1 भ्रष्ट कर्मचारियों/ अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होने पर परिवादी को ट्रेप रिकॉर्डर उपलब्ध करवाकर मांगी जाने वाली राशि का सत्यापन करवाया जाता है, तत्पश्चात मांग का सत्यापन सही पाये जाने पर स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में ट्रेप का आयोजन किया जाता है।
- 2 ट्रेप आयोजन के पश्चात भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का मामला बनने पर नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रधान आरक्षी केन्द्र, जयपुर पर दर्ज की जाती है। तत्पश्चात विधिक प्रावधानों के अनुसार स्वतन्त्र रूप से अनुसंधान करवाकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, एवं अन्य सुसंगत विधिक के तहत आरोप प्रमाणित पाये जाने पर राज्य सरकार द्वारा स्थापित राज्य के विशिष्ट न्यायालयों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं।
- 3 इसी प्रकार पद का दुरुपयोग/ आय से अधिक सम्पत्ति के मामलों में भी निष्पक्ष अनुसंधान करवाकर उक्त विशिष्ट न्यायालयों में आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं।
- 4 भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों की प्राथमिक जाँच कराने का प्रावधान है। ब्यूरो के अधीन चौकियों में परिवादों में जाँच/सत्यापन कार्य कराया जाता है। यदि किसी लोकसेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों का परिवाद प्रस्तुत होता है, तो उसके विरुद्ध परिवाद में लगाये गये आरोपों की प्राथमिक जाँच करवाकर सत्यापन करवाया जाता है। परिवाद में लगाये गये आरोपों का सत्यापन होने पर ही प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने की कार्यवाही की जाती है, अन्यथा परिवाद के तथ्य मिथ्या अथवा अप्रमाणित पाये जाने की स्थिति में कार्यवाही नस्तीबद्ध कर दी जाती है।

- 5 ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु सूत सूचनाओं के आधार पर भी कार्यवाही की जाकर आय से अधिक संपत्ति के प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किये जाते हैं।
- 6 इसी प्रकार भ्रष्टाचार के उन्मूलन हेतु समय समय पर आकस्मिक चैकिंग कर भ्रष्टाचार के मामले पाये जाने पर नियमानुसार नियमित अभियोग दर्ज करवाये जाते हैं।